ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

कोरोनाः आपदा या अवसर

रहीम मियाँ
एसिसटेंट प्रोफेसर
बानारहाट कार्तिक उराँव हिन्दी गवर्मेंट कॉलेज
बानारहाट, जलपाईगुड़ी, प.बं.
रिसर्च स्कोलर
लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी
फगवाड़ा, पंजाब

आज धीरे-धीरे पूरा संसार कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। घर-घर डर का साया छाया हुआ है। 'जान बचे तो लाखों पाय' वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है। विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित करने के पश्चात विश्व के सभी देशों के लिए कोरोना सिर दर्द बन गया है। चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस ने पूरे विश्व को अपना घर बना लिया है। कोई इसे मानव-निर्मित तो कोई इसे प्राकृतिक मान रहा है। सबके अपने-अपने तर्क है। एक बात तो तय है कि यह वायरस न तो अमीरी देखता है न गरीबी, न जात देखता है न विरादरी, न रंग देखता है न धर्म। इसके सामने सब बराबर। समानता का सिद्धांत लेकर तो यही आया है। यह सबसे ताकतवर है। इसने तो भगवान हो या अल्लाह सबके दरवाजें बन्द करवा दिये। अब यही तय करता है - कौन रहेगा और कौन जायेगा? पूरे विश्व के वैज्ञानिक हैरान, परेशान हैं। मानव, मानव से डर रहा है। कौन अपना, कौन पराया, सभी एक-दूसरे से डर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की तो लाशें तक घरवालों को नसीब नहीं हो रही हैं। कोरोना बार-बार हमें बता रहा है- 'हे मानव तुम्हारी सारी वैज्ञानिक प्रगति मेरे सामने बेकार है।' यह हमें हमारी औकात बता रहा है। हमने इतनी प्रगति कर ली है कि पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, किन्तु आँखों से न दिखने वाले एक सूक्ष्म जीव ने हमारी नींद उड़ा कर रख दी है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। शायद समय रहते हम इसका तोड़ भी

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

निकाल लें, किन्तु इसने हमें यह बता दिया है कि हमारी वैज्ञानिक प्रगति आज भी शून्य ही है।

ऐसा नहीं है कि संसार में आपदा पहली बार आई हो। इतिहास के पन्नों से लेकर दादा-दादी के किस्सों कहानियों तक ऐसी कई आपदाओं की कहानियाँ सुनी एवं सुनाई जा चुकी हैं। कोरोना नाम के आपदा की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसे समय में आई है जब हमारा विश्व पूरी तरह भूमंडलीकृत हो चुका है। भारत जैसे विकासशील देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड जैसे विकसित देशों की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भूमंडलीकरण की यह विशेषता है कि इसमें कुछ भी लोकल नहीं रहता, यहाँ सब कुछ ग्लोबल हो जाता है। इसलिए विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का चरमराना विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी है। इसे समझने की जरूरत है। हम यह भलिभांति जानते हैं कि हमारे देश में घटने वाली प्रत्येक घटना दूर देश में बैठे प्रथम विश्व के आकाओं द्वारा संचालित होती है।

चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस ने लोकल से ग्लोबल का रूप महज कुछ महीनों में ही ले लिया। जब यह वायरस चीन में तबाही मचा रहा था, हम इसे चीन की लोकल समस्या मान कर खिल्ली उड़ा रहे थें। चीन के खान-पान का मजाक बना रहे थें। हमने उस समय तनिक भी नहीं सोचा कि चीन की समस्या हमारी समस्या बनने में देर नहीं लगेगी। हमें उसी समय इसकी भयंकरता को भाँपते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए थे, किन्तु हम उस समय ट्रंप का स्वागत करने और विदेशों में फँसे लोगों को जहाज में भर-भर कर लाने में व्यस्त थें। जिन लोगों को भी उस समय बाहर से लाया गया, न तो उनको क्वारेन्टिन ही किया गया और न उनके टेस्ट कराने की व्यवस्था ही की गई। यह अलग बात है कि उस समय तक हमारे पास न तो टेस्ट किट ही उपलब्ध था और न हम कोरोना वायरस के स्वरुप से ही परिचित थें। हमने चीन से सबक नहीं लिया, न ही हमने इटली से कुछ सीखा। हमने खतरे को गंभीरता से लिया ही नहीं। क्या करते हमें तो मध्यप्रदेश में सरकार जो बदलनी थी। हम जगे, हमारी आँखें खुली और फिर मानव कर्फ्यू की घोषणा हो गई। मीडिया से

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

लेकर पार्टी प्रवक्ताओं ने यह दावा किया कि एक दिन के कर्फ्यू से कोरोना समाप्त हो जायेगा। कोरोना के 20 से 24 घंटे जीवित रहने की अटकलें लगाई गई। फिर अचानक से दौर शुरु हुआ लॉकडाउन का। एक ही रात की घोषणा ने रात भर में ही लॉकडाउन को लागू कर दिया। कुछ दिनों तक यही हाल रहा, फिर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में प्रधान सेवक द्वारा कभी ताली, थाली बजवाने का आग्रह किया गया तो कभी दीप जलाकर सम्मान देने की बात कही गई। देशवासियों ने हृदय से इस फैसले का स्वागत किया। साधारण जनता के दिमाग में यह बात भी भरी गई कि ताली, थाली, घंटे, घड़ियाल के बजने से एक तरंग की सृष्टि होती है जिससे कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। ऐसे समय में कुछ नेता बिना पढ़े ही जैव वैज्ञानिक भी बन गये और उन्होंने तो गौमूत्र में भी कोरोना का इलाज ढूँढ लिया, तो किसी ने कोरोना देवी की कल्पना कर पूजा करने की हिदायत तक दे दी। खैर जो भी हो, लॉकडाउन के कारण सरकारी खजाने पर भार बढ़ता जा रहा था, गरीब जनता के लिए कई हजार करोड़ के पैकेज की घोषणाएँ हुई, कई चीजों में रियायते दी गई, मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। किन्तु, इसी समय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के डी. ए. फ्रीज करने की घोषणा भी हुई और संसदों के MLAD जैसे फंड को भी समाप्त कर दिया गया। चीन से आयातित पी.पी.ई कीट में भी नेताओं द्वारा धाँधली की गई। एक बात समझ से परे लगी कि एक ओर देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दूसरी ओर सरकार इसे अवसर बनाते हुए अपने चहेते उद्योगपतियों के करीब आठ लाख करोड़ लोन के मॉफी की घोषणा आखिर किस आधार पर कर रही हैं?

पूरे देश में जहाँ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तीन महिनें में दो लाख के करीब पहुँची थी, अनलॉक के बाद तो जुलाई के मध्य तक दस लाख का दायरा पार कर चुकी है। इस कोरोना ने हमें बता दिया कि हमारे देश का स्वास्थ विभाग कितना पीछे है। जब देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, हमारे पास न तो आई, सी. यू. की प्रयाप्त संख्या थी, न देश में रोगियों के इलाज के लिए प्रयाप्त बिस्तर। यह अच्छी बात है कि पिछले चार महीनें में हमने काफी नये आई. सी. यू.

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

मशीनों का आयात कर लिया है और माक्स और सैनेटाइजर के निर्माण के मामले में हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। किन्तु अभी भी कई देशी कम्पनियों द्वारा पी.पी.ई. बना लेने के बाद भी इसकी पूरी आपूर्ती नहीं हो पा रही हैं। ऐसे समय में अपने देश के ही कई कम्पनियों ने माक्स और सैनेटाइजर को काफी ऊँची कीमत में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दस रुपये की साधारण मास्क 300 रुपये तक में बेची गई और 20 रुपये का सैनेटाइजर 200 रुपये में। फिर भी देश में इन दो आवश्यक चीजों की प्रयाप्त आपूर्ती नहीं हो पाई। सरकार द्वारा ऐसे समय में सोने पर 3% तो सैनिटाईजर पर 18% GST लगाना इसे अवसर बनाना ही तो है।

आज जब कोरोना संक्रमण की संख्या में बेतहासा वृद्धि हो रही है, हमें इससे आत्म निर्भर होकर लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे देश में अभी तक रेपिड टेस्ट चालू नहीं हो पाया है। जरा सोचिए! आज जहाँ एक दिन में दो लाख टेस्ट हो रहा है, वहाँ लगभग 35,000 लोग संक्रमित पाये जा रहे हैं। अगर रेपिड टेस्ट हो और हर दिन एक करोड़ भारतीयों का टेस्ट किया जाय तो कितने लोग हर दिन संक्रमित मिलेंगे? नौबत ऐसी भी आ सकती है कि अस्पताल क्या सड़कों पर भी जगह नहीं मिले। इधर कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उधर हर चीज महंगी पे महंगी होती जा रही है। नर्सिंग होम वालों ने तो इसे अवसर बनाते हुए मनमाना चार्ज वसूलना शुरु कर दिया है। एम्बुलेन्स जैसी सुविधाएँ भी इतनी महंगी हो गई है कि आम जन अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी हाल ही में खबर दिखाया गया जिसमें कई कोरोना मरीजों की मौत इसलिए हो गई चूँकि उन्हें किसी भी अस्पताल में जगह ही नहीं मिली, और उधर प्रधान सेवक द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमने कोरोना से लड़ने में 150 देशों की मदद की। आज कई कम्पनियाँ बन्द हो चुकी है। सब्जी, राशन, गैस, तेल जैसे आवश्यक चीजें की कीमतें रोज बढ़ रही है। घर वापस आए बेरोजगार मजदूरों के रोजगार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। हम आज आपदा के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमारा बचे रहना ही हमारे लिए चुनौती बन गई है।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

इस आपदा को मीडिया तंत्र ने अवसर बनाकर अपनी टी. आर. पी. खूब बढ़ाई है। शुरुआत में तो मीडिया ने यह प्रचार किया मानो भारत में आते ही कोरोना की मौत 24 घंटे में हो जायेगी। प्रधान सेवक द्वारा भी 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाने की बात कही गई। फिर कोई चैनल हमें कोरोना के नाम से डराता रहा तो कोई वायरस की नयी- नयी जानकारी देता रहा। फिर अचानक से दौर शुरु हुआ मरकज का। मीडिया ने कोरोना को मरकज से जोड़कर साम्प्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की, फिर मजदूरों का मामला मीडिया के केन्द्र में आ गया। यह वह समय था जब मजदूर वर्ग के धैर्य का बाँध टूट चुका था और सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापसी के लिए कुछ उपाय न करने पर वे सपरिवार पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थें। मजदूरों के घर वापसी के दृश्य ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मजदूर सड़क पर कहीं पैदल चलते हुए मरे तो कहीं रेल पटरी में कट कर। कहीं मजदूर सड़क दुर्घटना के शिकार हुए तो कहीं वे भूखे मरने को विवश हुए। राज्य और केन्द्र की सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल खेलती रही, मरने वाले मरते रहें। ऐसी परिस्थिति को भी कई गाड़ी चालकों ने अवसर बनाया और पैदल चल रहे मजदूरों को अपनी गाड़ी में जगह देने के लिए एक-एक से दस से बारह हजार रुपये वसूले। ये मजदूर घर वापसी को विवश हुए क्योंकि इनके मालिकों ने इन्हे बिना काम के वेतन देने से इंकार कर दिया। सरकार के आश्वासन के बाद भी इन मजदूरों को इनका वेतन नहीं मिला। जिन मजदूरों के मेहनत से कल-कारखाने चलती है और पूँजीपति करोड़ों कमाते हैं, क्या उनके पास इतनी भी पूँजी नहीं थी कि वे तीन महीनें मजदूरों को बिना काम वेतन दे सकते? मजदूरों के पक्ष में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। समय रहते ही लॉकडाउन के बीच कुछ दिनों की ढ़ील देकर मजदूरों को घर वापस भेजने का कार्य किया गया होता तो ये मजदूर दो महीनों तक शहरों में फँसे रहकर संक्रमित नहीं होते। सरकार की नींद बड़ी देर से खुली और फिर मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। जहाँ सरकार विदेशों से अमीरों के लाने के लिए स्पेशल हवाई जहाज की व्यवस्था कर सकती थी,

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

उसी सरकार को मजदूरों के लिए रेल सेवा चालू करने में कई दिन लग गये। इस पर भी आर्थिक संकट का राग अलापा जाता रहा।

देश की आर्थिक हालत तो कोरोना के पहले से ही खराब हो चुकी थी, GDP कई वर्षों के निम्न स्तर पर पहुँच चुकी थी, देश की अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बैंकों का विलय किया जा रहा था। कोरोना तो ऐसे समय में सरकार के लिए अवसर बनकर आया। सरकार की सारी नाकामियों का जिम्मा अब बड़ी आसानी से कोरोना के माथे मढ़ा जा सकेगा। लोगों का ध्यान कोरोना की ओर है और सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया फिर से तेज कर दी है। इस बीच कोयले के खानों का निजीकरण कर दिया गया। कई स्टेशनों को पूँजीपतियों के हाथों बेच दिया गया। फिर से रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। जिसप्रकार सरकार एक-एक कर सरकारी तंत्र का निजीकरण कर रही है और सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है, हमारे अगले जेनेरेशन के लिए सरकारी नौकरियाँ बचेगी नहीं। निजीकरण होना चाहिए। 1990 के दशक में जब देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, तात्कालीन सरकार द्वारा निजीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाकर ही देश को बचाया जा सका था। किन्तु, यह भी सच है कि निजीकरण और सरकारीकरण के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। हर सरकारी तंत्र का निजीकरण कर प्राइवेट कम्पनी को बेच देना किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता। आज जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, आप देखिये जिसे हम कोरोना वेरियर कह रहे हैं, वे सब अधिकांशतः सरकारी तंत्र के है, चाहे वे डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस हो, या चपरासी हो। देश की इस संकट की घड़ी में कौन आगे है? ज्यादातर प्राइवेट वाले तो अपना क्लीनिक बंद कर दुबक गये है। कई प्राइवेट नर्सिंग होम बंद कर दिये गये है। जो खुले है वे भी इलाज के नाम पर पैसे छाप रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप के बाद ही कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को कोरोना अस्पताल बनाया जा सका। पूरे देश में लाखों लोगों को क्वारेन्टीन किया गया। ये सारे क्वारेन्टीन सेन्टर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, भवनों को बनाया गया। क्यों किसी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या अस्पताल को क्वारेन्टीन सेन्टर नहीं बनाया गया? एक दो अपवाद

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

हो सकते हैं। किन्तु यह सच है कि आज पूरे देश को सरकारी तंत्र द्वारा ही बचाया जा रहा है।

कोरोना के कारण विश्व स्तर पर कच्चे तेलों के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, इसको अवसर बनाते हुए अच्छा फायदा उठाया गया और देश में हर दिन तेल की कीमतें बढ़ाई जाती रही। इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल को पार कर गई। एक ओर जहाँ सरकार आर्थिक तंगी का राग अलाप रही है, उधर बिहार और बंगाल जैसे राज्य में चुनाव की तैयारी के लिए करोड़ों खर्च की जा रही है। केवल बिहार जैसे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए 72,000 LED SCREEN लगवाया गया, जहाँ एक LED SCREEN की कीमत 20 से 22 हजार बतायी जा रही है। एयर इंडिया जैसी कम्पनी ने भी कोरोना को अवसर बनाते हुए अपने कई कर्मचारियों को बिना वेतन के पाँच वर्ष के लिए आवश्यक छुट्टी पर जाने की घोषणा सुना दी है।

यह सच है कि कोरोना से लड़ाई बिना अर्थ के संभव नहीं। सरकार द्वारा लोगों से आर्थिक मदद के लिए PM CARE और CM RELEIFE FUND में दान कर सरकार की मदद करने की अपील की गई। लोगों ने अपनी काबिलियत के अनुसार दान भी दिया। इस पर भी कॉर्पोरेट जगत के CSR फंड को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच तानातनी शुरु हो गई। अंत में केन्द्र ने यह निर्णय दिया कि कॉर्पोरेट जगत का CSR फंड केवल PM CARE में दिया जा सकता है, किसी राज्य सरकार को नहीं। इतना होने के बावजूद जब खर्चे और हिसाब की बात आई, राज्य और केन्द्र दोनों की सरकारों ने कन्नी काट लिया। अब कोरोना को भूलकर दोनों सरकारें चुनाव अभियान में जुट गई है।

आपको शायद याद होगा कोरोना से ठीक पहले सरकार CAA और NRC के मुद्दे पर चतुर्दिक घिर चुकी थी। पूरे देश में CAA और NRC के खिलाफ़ आवाज़ें बुलन्द की जा रही थीं। दिल्ली के शाहीन बाग में दो महीनों से आन्दोलन जारी था। सरकार की कूटनीति के बावजूद शाहीन बाग से आन्दोलनकारियों को हटाया नहीं

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

जा सका था। CAA और NRC जैसे मुद्दों ने सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया था, ऐसे में कोरोना की लहर ने सरकार को बचा लिया। पूरे देश में जारी लॉकडाउन ने इन मुद्दों को सस्ते बस्ते में भर दिया। इसी लॉकडाउन के बीच एक दिन शाहीन बाग को भी खाली करवा लिया गया। खैर, इस महामारी में शाहीन बाग को तो खाली होना ही था, साथ ही सरकार का सिर दर्द भी खत्म हो गया, जनता भी सारे मामलों को भूल गई। इसी बीच चीन के गलवान घाटी की समस्या ने हमारा ध्यान कोरोना से खींचकर अपनी ओर कर लिया। कोरोना फिर मुद्दे से बाहर हो गया। लद्दाख के गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुवल कॉन्ट्रोल को लेकर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस निहत्थे झड़प में भी हमारे 20 जवान शहीद हो गये। कई दिनों तक मीडिया में चीन और भारत की लड़ाई चलती रही और हम रोज विजयी होते रहें। कई हथियारों के नाम भी हमने पहली बार सुना, इन चैनलों ने युद्ध की नीतियाँ भी सीखाई। इन चैनलों द्वारा रोज चीन और भारत के सैन्य ताकतों की तुलना करवाया गया। चीन के पास ऐसा हथियार है तो भारत के पास वैसा। अंत में भारत सरकार द्वारा 59 चीनी एप को बन्द कर शहीदों की शहादत का बदला ले लिया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण की संख्या चुपके से 10 लाख के पार पहुँच गई। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के डॉन विकास दुबे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मीडिया ने इसे जमकर तूल दिया, कोरोना को फिर से भूला दिया गया। फिर एक दिन विकास दूबे का चेप्टर भी बन्द हो गया। उसके इनकाउन्टर के साथ ही कई सारे राज भी दफन कर दिया गया।

आपदा को अवसर बनाने में देश के बड़े-बड़े प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जब पिछले पाँच महिनें से स्कूल- कॉलेज बन्द है, फिर भी बच्चों से पूरी फीस के साथ-साथ बस फेयर भी वसूला जा रहा है। कई स्कूलों में पैरेन्टस फोरम द्वारा विरोध करने पर कुछ रियायते दी गई। बच्चों से पूरी फीस लेने के बावजूद प्राइवेट स्कूल के मालिकों द्वारा शिक्षकों को आधी सैलरी दी जा रही है। आप इन स्कूल संगठनों के खिलाफ़ आवाज भी नहीं उठा सकते। कई राज्य सरकारें इस मामले में चुप्पी साधे बैठी हैं। आखिर ये बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल, कॉलेज

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

किसी न किसी पूँजीपति घरानों के है, और ये पूँजीपति घराने ही तो हर पार्टी के डोनेशन बैंक है। सरकारें तो इनसे ही चलती है। ऑनलाईन क्लास के नाम पर जो चल रहा है, उससे बच्चों को कितना फायदा होगा, यह तो समय ही बतायेगा। वैसे भी जितने प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है, वहाँ तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, किन्तु देश के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूल-कॉलेज के बच्चों के पास न तो ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध है, न ही सरकार को उनकी कोई चिंता ही है। उन सबकी क्लास तो भगवान भरोसे ही चल रही है।

इस आपदा को अवसर बनाने में बाबा रामदेव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक ओर जहाँ पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोरोना की दवा के लिए दिन-रात लगे हुए है। कई देशों में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, अचानक से एक दिन बाबा जी अपना प्रोडक्ट लेकर मीडिया से मुखातिब हो जाते हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है और उनका प्रोडक्ट 100% कोरोना मरीज को ठीक करता है। आयुष मंत्रालय द्वारा यह तर्क दिया गया कि उन्होंने बाबा जी की दवा को खाँसी और इम्युनिटी बुस्टर के लिए प्रमाणित किया है, कोरोना की दवा के लिए नहीं। इसके बावजूद बाबा जी द्वारा देश के सामने इसे कोरोना की दवा कहकर प्रचारित करना सरासर अन्याय है। बाबा जी पर तो झूठ बोलकर देश को गुमराह करने, लोगों की भावनाओं से खेलने, जालसाजी करने जैसे संगीन अपराध की धारा लगनी चाहिए। किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं न – 'सरकार मेहरबान तो गधा पहलवान'।

कई महीनों के लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को विवश होकर देश को ऑनलॉक करना पड़ा। ऑनलॉक के बाद तो कोरोना ने दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हासिल की। सरकार द्वारा आत्म निर्भर का नारा देकर हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे भी 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 20-30 लाख लोग मर भी गये तो सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं।

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 13 July 2020

उनकी तो बस कुर्सी बचनी चाहिए। एक फिल्मी डायलॉग है न – 'अपना काम बनता, भाड़ में जाये जनता।' अब तो केन्द्र सरकार ने कोरोना से पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है और सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी गई है। सरकार का दायित्व तो बस महीनें में एक बार राज्य के मुख्य मंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग कर कोरोना का जायजा लेने और मन की बात करने तक सीमित हो चुका है। अभी कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं है और उधर मैडम नीता अंबानी यह घोषणा कर रही है कि वैक्सीन आते ही वह इसे हर गरीब तक पहुँचाने में मदद करेगी। गरीब जनता इसकी चिंता न करें। अब इसे हम नीता मैडम का गरीबों के प्रति दरिया दिली समझे या इसके पीछे भी कोई विज़नेश पॉलिसी है, कह पाना मुश्किल है। यह वहीं पूँजीपति वर्ग है जो उस समय चुप्पी साधे बैठी थीं जब सड़क पर लाखों मजदूर विवश होकर पैदल चल रहे थें और जगह-जगह मारे जा रहे थें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना एक ओर जहाँ गरीबों के लिए आपदा बनकर आया, वहीं यह नेताओं और पूँजीपतियों के लिए अवसर। आज जहाँ पूरे विश्व में संक्रमण की संख्या 14 मिलियन पार कर चुका है और 6 लाख लोग जुलाई के मध्य तक मारे जा चुके हैं, हमारा देश भी धीरे-धीरे प्रथम स्थान प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। संक्रमण की यही तेजी रही तो हमें ब्राजील और अमेरिका को पार कर नम्बर वन बनने से कोई नहीं रोक पायेगा।

Copyright @ 2020 Authors